निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 413) पटना, मंगलवार, 31 मार्च 2015

सं0 को0प्र0/कम्प्यूटर-7/2010(खण्ड)-3332-वि0

वित्त विभाग

संकल्प

31 मार्च 2015

विषयः—भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में कोषागारों तथा वित्त विभाग के आधुनिकीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन (CFMS) योजना के कार्यान्वयन हेतु मनोनयन (Nomination) के आधार पर National Institute of Smart Governance(NISG)को परामर्शी के रूप में रू0 94.90 लाख (सेवाकर अलग से) की अनुमानित लागत पर Two stage(Conceptualisation & Architecture) के कार्य हेतु Consultant चयनित करने के संबंध में।

वर्ष 2006 से केन्द्रीय कम्प्युटर प्रणाली को लागू किया गया। इसमें एक केन्द्रीय Bihar Revenue Administrative Intranet (BRAIN) Data Centre की स्थापना की गई । BRAIN डाटा सेंटर में स्थित सरवरों से सभी कोषागारों को Bihar State Wide Area Network (BSWAN) से जोड़ा गया। इसी BRAIN DC के सरवर पर सभी application यथा Comprehensive Treasury Management Information System(CTMIS), Integrated Workflow Management System(IWDMS), VAT-MIS आदि को स्थापित किया गया ।

BSWAN से 38 जिलों तथा 534 प्रखण्डों को जोड़ा गया V-SATतथा LAN Extender को Standby के लिए रखा गया। CTMIS सॉफ्टवेयर को विभिन्न चरणों में विभिन्न कोषागारों में लागू किया गया ।

वर्तमान में CTMIS में कार्यरत कुछ मुख्य मॉड्यूल इस प्रकार है :—

1. Budget Module
2. GPF/NPS Module
3. Payment Module
4. Treasury/Bank Interface Module
5. Loan and Advance Module

परंतु भारत सरकार द्वारा **प्रस्तावित् माड्यूलों** में से अबतक बहुत सारे मॉड्यूल कार्यरत नही है, जिन्हे नए सॉफ्टवेयर के जरिए लगाया जाना है ।

इनमे से कुछ महत्वपूर्ण माड्यूल इस प्रकार हैः

1 Human and Resource Management System
2 Pension Module
3 Virtual Treasury Module
4 Financial Data Warehouse Module
5 Accounts and Allotment Module
6 Fund Management Module
7 E-Audit
8 Receipt Module

साथ ही, वर्तमान में कार्यरत मॉड्यूल करीब आठ साल पुरानी हो गई है और उसमे लगी हुई Technology धीरे–धीरे obsolete हो रही है। अतः पुराने सॉफ्टवेयर को हटाकर नए सॉफ्टवेयर या पुराने में ही कुछ परिवर्तन कर कार्य हेतु उपर्युक्त बनाने की आवश्यकता है।

2. अन्य राज्यों की भाँति बिहार में भी भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित NeGP के अन्तर्गत मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के विभिन्न कोषागारों में, वित्तीय प्रबंधन योजना का आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में, वर्ष 2011–12 में एक Detailed Project Report (DPR) भारत सरकार को समर्पित की गई थी जिसके मान्य होने पर राज्य को वित्तीय वर्ष 2011–12 में एक किस्त लगभग 11.40 करोड़ (ग्यारह करोड़ चालीस लाख रुपए) की राशि विमुक्त की जा चुकी है।

3. विभागीय स्तर पर हीं एक RFP तैयार कर वर्ष 2013 के फरवरी महीने में एक निविदा प्रकाशित की गई। जिसमें एकमात्र बिड प्राप्त होने के कारण निविदा को अंतिम रुप नही दिया जा सका ।

4. राज्य सरकार के सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा विभाग के परामर्शानुसार Director General, NIC को पत्र लिखकर यह **जानकारी हासिल किया गया** कि क्या मिशन मोड के तहत लागू किए जाने वाले सभी माड्यूलों का कार्यान्वयन NIC के द्वारा किसी राज्य में किया जा रहा है । NIC, पटना द्वारा महाराष्ट्र तथा झारखंड सरकार में कार्यरत सॉफ्टवेयर में से किसी एक को चयनित कर उसे बिहार सरकार के कोषागारों के आवश्यकतानुसार Customise कराए जाने का सुझाव दिया गया।

5. दिनांक 26.11.2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन मोड के तहत कोषागारों के कम्प्युटराईजेशन हेतु मुख्य बिन्दुओं पर निर्णय लेने हेतु बैठक की गई ।

उक्त बैठक में National Institute of Smart Governance (NISG) को Comprehensive Financial Management System (CFMS) के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी रखने पर एकमत बना।

NISG कम्पनीज अधिनियम की धारा–25 के अंतर्गत निबंधित not for profit कम्पनी है ।

NISG e-Governance से संबंधित सरकारी परियोजनाओं का निर्वहन करता है। उक्त संस्था किसी भी टेडर में भाग नहीं ले सकती है । केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं मे यह संस्था Nomination के आधार पर ही अपने कार्य का निर्वहन करती है ।

6. तत्काल मात्र दो चरण का ही NISG से कार्य करवाने पर माननीय मंत्री (वित्त विभाग) द्वारा सहमति दी गई हैः

(क) Conceptualisation – इस चरण में NISG की expert team तीन संभावनाओं में से सबसे उपर्युक्त पर अपना विचाार प्रस्तुत करेगी। तीन संभावनाएँ निम्नांकित है–

(a) मिशन मोड के अन्तर्गत प्रस्तावित मॉड्यूलों को वर्त्तमान में कार्यरत CTMIS सॉफ्टवेयर में ही जोड़े जाने की संभावना ? या

(b) भारत सरकार की संस्था NIC द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर अगर मिशन मोड के प्रस्तावित मॉड्यूल के समान हो और किसी राज्य में सफलतापूर्वक कार्यरत है तो क्या उसे बिहार में भी Customize करके लगाना संभव है? या

(c) नए सिरे से RFP तैयार करके इसे प्रकाशित किया जाय और नए सिरे से निविदा प्राप्त कर नयी सॉफ्टवेयर लगाने हेतु System Integrator का चयन किया जाय।

(ख) Architecture – में प्रस्तावित सॉफ्टवेयर हेतु

(a) Functional Architecture
(b) Process Architecture
(c) Technology Architecture
(d) People Architecture
(e) Resource Architecture

का अध्ययन NISG के expert की टीम करेगी और निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी राय रखेगीः–

(a) Geographical and Functional Coverage
(b) Solution Architecture Overview
(c) Implementation Strategy, Model & Plan
(d) Technology Solution
(e) Alternatives/Options (COTS Vs BESPOKE Vs Both) for Implementation
(f) Data Migration Strategy
(g) Project Financials

उक्त कार्य के लिए कुल राशि रु0 94.90 लाख रुपए (सेवाकर अलग से) की माँग की गई है। इस राशि हेतु NISG के साथ हुई चर्चा के उपरांत प्रस्ताव दिया गया है।

7. **समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सम्यक विचारोपरांत,** भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में कोषागारों तथा वित्त विभाग के आधुनिकीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन (CFMS) योजना के कार्यान्वयन हेतु मनोनयन (Nomination) के आधार पर National Institute of Smart Governance (NISG) को परामर्शी के रूप में रू0 94.90 लाख (सेवाकर अलग से) की अनुमानित लागत पर Two stage (Conceptualisation & Architechture) के कार्य हेतु Consultant चयनित **किया जायेगा** ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच0 आर0 श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 413-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in